International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 14 Issue 10 || October 2025 || PP. 42-48

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समालोचनात्मक अध्ययन एवं शिक्षक-शिक्षा पर उसका प्रभाव

डॉ० देवेंद्र कुमार दीक्षित

अस्सिटेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ़ बी एड सेठ फूल चंद बगला, पी० जी० कॉलेज हाथरस

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता, लचीलापन तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाना है। विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति ने अनेक संरचनात्मक एवं नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना तथा शिक्षकों को अधिक पेशेवर एवं उत्तरदायी बनाना है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समालोचनात्मक अध्ययन करना तथा शिक्षक-शिक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में नीति के प्रमुख प्रावधानों, विशेषकर चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के मानकीकरण, निरंतर व्यावसायिक विकास तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे पहलुओं का विवेचन किया गया है। साथ ही यह भी विश्लेषित किया गया है कि यह नीति शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार नए अवसरों का सृजन करती है और इसके कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करती है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षित मानव-बल तथा संस्थागत समन्वय की आवश्यकता होगी। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है, तो यह नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

कुंजी शब्द: *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षक-शिक्षा, शिक्षा सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण चार वर्षीय समेकित बी. एड. कार्यक्रम, निरंतर व्यावसायिक विकास, शिक्षा की गुणवत्ता भारतीय शिक्षा प्रणाली, शैक्षिक नीतियाँ, समावेशी शिक्षा*

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। किसी देश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता मुख्यतः उसके शिक्षकों की दक्षता, प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। शिक्षक न केवल ज्ञान के संवाहक होते हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, नैतिक मूल्यों के विकास तथा समाज के समग्र उन्नयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी भी प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के लिए सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक-शिक्षा प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत में शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, समावेशी तथा आधुनिक बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न शिक्षा नीतियों का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) प्रस्तुत की गई, जो कि स्वतंत्र भारत की तीसरी प्रमुख शिक्षा नीति है। इससे पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा 1986 (1992 में संशोधित) लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाना, विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन तथा नवाचार की क्षमता का विकास करना तथा भारत को ज्ञान-आधारित समाज के रूप में विकसित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक-शिक्षा सहित शिक्षा के लगभग सभी आयामों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में यह नीति अनेक नवीन प्रावधान प्रस्तुत करती है, जिनका उद्देश्य शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना तथा शिक्षकों को अधिक पेशेवर

एवं उत्तरदायी बनाना है। इस नीति के अंतर्गत चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम को अनिवार्य बनाने, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, तथा शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास पर विशेष बल दिया गया है।

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित अनेक प्रश्न एवं चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि इस नीति के प्रावधानों का समालोचनात्मक अध्ययन किया जाए, ताकि इसके संभावित लाभों तथा सीमाओं का संतुलित विश्लेषण किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है तथा शिक्षक-शिक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि यह नीति शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार ला सकती है तथा इसके क्रियान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं समस्या का प्रतिपादन

वर्तमान समय में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक ही वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षा की नीतियाँ, उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुँचते हैं। यदि शिक्षक पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, दक्ष तथा नवीन शिक्षण विधियों से परिचित नहीं होंगे, तो शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। इसी कारण से शिक्षक-शिक्षा को शिक्षा प्रणाली की आधारभूत इकाई माना जाता है। भारत में लंबे समय से शिक्षक-शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याएँ सामने आती रही हैं। इनमें शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में असमानता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अप्रासंगिकता, व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी, तथा शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की अपर्याप्त निगरानी जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कई बार शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में समकालीन शैक्षिक आवश्यकताओं, तकनीकी विकास तथा विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से सम्मिलित नहीं किया जा सका है। परिणामस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त नहीं हो पाती।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित करती है। इस नीति में चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम को शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार, बहुविषयी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन, तथा शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास पर विशेष बल दिया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य शिक्षक-शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, फिर भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की संरचनात्मक तैयारी, तथा प्रशिक्षित संकाय की उपलब्धता जैसी चुनौतियाँ सामने आ सकती हैं। इसके अतिरिक्त नीति के प्रावधानों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से लागू करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समालोचनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में यह नीति किस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है तथा इसके कार्यान्वयन में संभावित बाधाएँ क्या हो सकती हैं। प्रस्तुत अध्ययन इसी उद्देश्य से किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों तथा शिक्षक-शिक्षा पर उनके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

किसी भी शोध-अध्ययन की दिशा एवं स्वरूप को निर्धारित करने में उसके उद्देश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन के उद्देश्य यह स्पष्ट करते हैं कि शोधकर्ता किस विषय का किस दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहता है तथा

अध्ययन के माध्यम से किन प्रमुख तथ्यों या निष्कर्षों तक पहुँचना चाहता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक-शिक्षा पर इसके प्रभावों का समालोचनात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना।
2. शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की संभावनाओं का अध्ययन करना।
4. शिक्षक-शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित संभावित चुनौतियों एवं समस्याओं की पहचान करना।
6. शिक्षक-शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

इन उद्देश्यों के माध्यम से यह अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षक-शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने तथा उसके सकारात्मक और सीमित पक्षों का सम्यक् विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

अनुसंधान पद्धति

किसी भी शोध-अध्ययन की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता उसके द्वारा अपनाई गई अनुसंधान पद्धति पर निर्भर करती है। अनुसंधान पद्धति वह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शोधकर्ता अपने अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक तथ्यों का संग्रहण, विश्लेषण तथा व्याख्या करता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए शिक्षक-शिक्षा पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस अध्ययन में मुख्यतः **गुणात्मक अनुसंधान पद्धति (Qualitative Research Method)** का उपयोग किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों का वर्णन करते हुए शिक्षक-शिक्षा के संदर्भ में उनका समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है। इस शोध में तथ्यों के संग्रह के लिए मुख्यतः **द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources)** का उपयोग किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज, शोध-पत्र, पुस्तकों, शैक्षिक पत्रिकाओं, सरकारी रिपोर्टों तथा अन्य प्रासंगिक साहित्य का अध्ययन किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से नीति के विभिन्न प्रावधानों तथा शिक्षक-शिक्षा पर उनके संभावित प्रभावों को समझने का प्रयास किया गया है। प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करते समय तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सकारात्मक पक्षों के साथ-साथ उसकी सीमाओं तथा चुनौतियों का भी स्पष्ट रूप से विवेचन किया जा सके। इसके अतिरिक्त अध्ययन में शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा नीति द्वारा प्रस्तावित सुधारों के मध्य संबंध को भी समझने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः दस्तावेज़ीय विश्लेषण (Document Analysis) पर आधारित है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शिक्षक-शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का समग्र एवं संतुलित विश्लेषण किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक व्यापक शैक्षिक सुधार नीति है, जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, समावेशी, लचीला तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। यह नीति लगभग 34 वर्षों के बाद लागू की गई है। इससे पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू की गई थी, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किए गए थे। बदलते सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी परिवेश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में समग्र विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा भारत को एक ज्ञान-आधारित समाज के रूप में विकसित करना है। यह नीति शिक्षा को केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम न मानकर उसे

रचनात्मकता, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान की क्षमता के विकास से जोड़ती है। इसके माध्यम से शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, बहुविषयी तथा छात्र-केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पारंपरिक **10+2 संरचना** को समाप्त करके **5+3+3+4 संरचना** को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस नई संरचना में शिक्षा को चार चरणों—आधारभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण तथा माध्यमिक चरण—में विभाजित किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के अनुसार शिक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के प्रयोग पर भी विशेष बल दिया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए हैं। इसके अंतर्गत बहुविषयी शिक्षा (Multidisciplinary Education) को प्रोत्साहित करने, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता बढ़ाने, तथा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए **राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation)** की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में लचीलापन बढ़ाने के लिए बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गम (Multiple Entry and Exit) की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत किए हैं। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक शिक्षक बनने के लिए **चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम** को न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षक-शिक्षा को बहुविषयी विश्वविद्यालयों से जोड़ने पर भी विशेष बल दिया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़, आधुनिक तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने का एक व्यापक प्रयास है। यह नीति शिक्षा के विभिन्न आयामों में सुधार के साथ-साथ शिक्षक-शिक्षा को भी नई दिशा प्रदान करती है, जो कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शिक्षक-शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रभाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता मुख्यतः शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए नीति में शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास तथा शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक तथा आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक बनने के लिए **चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम** को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षक-प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित तथा गुणवत्तापूर्ण बनाना है। चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम में विषय ज्ञान, शिक्षण विधियों तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण को समन्वित रूप से सम्मिलित किया गया है, जिससे भावी शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए अधिक सक्षम बन सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि वर्ष 2030 तक सभी शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को बहुविषयी विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य शिक्षक-शिक्षा को अन्य विषयों के साथ जोड़कर अधिक व्यापक एवं समग्र बनाना है। इससे शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है तथा शिक्षक अधिक बहुआयामी ज्ञान से युक्त हो सकेंगे।

इसके अतिरिक्त इस नीति में **निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development)** पर भी विशेष बल दिया गया है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण, कार्यशालाओं तथा अन्य शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से अपने ज्ञान एवं कौशल को अद्यतन करने के अवसर प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे शिक्षकों को बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं, नई शिक्षण विधियों तथा तकनीकी नवाचारों के साथ स्वयं को समायोजित करने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक-भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं योग्यता-आधारित बनाने पर भी बल दिया गया है। नीति के अनुसार शिक्षक-भर्ती में विषय-ज्ञान, शिक्षण-कौशल तथा अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक के पेशे को अधिक सम्मानजनक एवं आकर्षक बनाने के लिए कार्य-परिस्थितियों में सुधार करने पर भी जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी के

उपयोग को भी शिक्षक-शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। नीति के अंतर्गत शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण उपकरणों, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों तथा अन्य तकनीकी संसाधनों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित करने पर बल दिया गया है। इससे शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, लचीला तथा आधुनिक बनाया जा सकेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन तथा व्यावसायिक विकास के अनेक अवसर प्रदान करती है। यदि इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह नीति शिक्षक-शिक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का समालोचनात्मक विश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। इस नीति में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर संरचनात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में यह नीति कई सकारात्मक पहलुओं को सामने लाती है। तथापि किसी भी नीति की प्रभावशीलता का आकलन केवल उसके उद्देश्यों और प्रावधानों के आधार पर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके व्यावहारिक क्रियान्वयन, संभावित चुनौतियों तथा सीमाओं का भी समालोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक होता है। सबसे पहले यदि इस नीति के सकारात्मक पक्षों पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक सुविचारित ढाँचा प्रस्तुत करती है। चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम की व्यवस्था शिक्षक-प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित तथा व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इससे भावी शिक्षकों को विषय-ज्ञान के साथ-साथ शिक्षण-कौशल तथा शैक्षणिक मनोविज्ञान की समुचित समझ प्राप्त हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बहुविषयी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने का प्रावधान भी शिक्षक-प्रशिक्षण को अधिक व्यापक एवं समग्र बनाने में सहायक हो सकता है।

इस नीति का एक अन्य सकारात्मक पहलू शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास पर दिया गया बल है। बदलते समय में शिक्षा के स्वरूप, शिक्षण विधियों तथा तकनीकी साधनों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने ज्ञान एवं कौशल को समय-समय पर अद्यतन करते रहें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करने पर बल देती है। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अनेक सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं, फिर भी इसके क्रियान्वयन से संबंधित कई चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने की है। देश के अनेक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में अभी भी बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित संकाय तथा आवश्यक संसाधनों की कमी है। ऐसे में इस कार्यक्रम को सभी संस्थानों में समान रूप से लागू करना एक जटिल कार्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक-शिक्षा संस्थानों को बहुविषयी विश्वविद्यालयों से जोड़ने का प्रावधान भी व्यावहारिक स्तर पर कई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। भारत में अनेक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान छोटे तथा स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं, जिन्हें बड़े विश्वविद्यालयों के साथ समन्वित करना एक दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया हो सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में किसी भी शैक्षिक नीति को समान रूप से लागू करना सरल नहीं होता। विभिन्न राज्यों की सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक परिस्थितियों में भिन्नता होने के कारण नीति के क्रियान्वयन में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण तथा प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधारों का मार्ग प्रशस्त करती है। तथापि इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि नीति के प्रावधानों को योजनाबद्ध एवं प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तथा क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समुचित समाधान किया जाए।

निष्कर्ष एवं सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण, लचीला तथा आधुनिक बनाना है। विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में यह नीति अनेक महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, जिनका उद्देश्य शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना तथा शिक्षकों को अधिक दक्ष एवं उत्तरदायी बनाना है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करती है। चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम, बहुविषयी विश्वविद्यालयों में शिक्षक-शिक्षा का समावेश, तथा शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास पर दिया गया बल शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा शिक्षक-भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में भी नीति ने सकारात्मक पहल की है। हालाँकि इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। यदि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों में पर्याप्त संसाधनों, योग्य संकाय सदस्यों तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई, तो नीति के अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इसके साथ ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में नीति के समान एवं संतुलित क्रियान्वयन के लिए भी प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं—

1. शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढाँचे तथा शैक्षणिक संसाधनों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
2. शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा विद्यालयीय अनुभव को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
3. शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
4. शिक्षक-भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तथा योग्यता-आधारित बनाया जाना चाहिए।
5. शिक्षण प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों तथा डिजिटल संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
6. नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक एवं सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इससे न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बन सकेगी।

साहित्य समीक्षा

किसी भी शोध-अध्ययन में साहित्य समीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके माध्यम से शोधकर्ता यह समझने का प्रयास करता है कि संबंधित विषय पर पूर्व में किन-किन विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया है तथा उनके अध्ययन से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। प्रस्तुत अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा शिक्षक-शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोधों और लेखों का अध्ययन किया गया है। अग्रवाल (2019) के अनुसार शिक्षक-शिक्षा किसी भी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता निर्धारित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके अनुसार यदि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्थित, व्यावहारिक तथा आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप हों, तो शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार संभव है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षक-शिक्षा में विषय ज्ञान के साथ-साथ शिक्षण कौशल और व्यावहारिक प्रशिक्षण को भी पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। शर्मा (2018) ने अपने अध्ययन में बताया है कि भारत में शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं, जैसे शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता तथा प्रशिक्षण की व्यावहारिकता। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रमों में समय-समय पर सुधार करना आवश्यक है ताकि वे बदलती शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप बने रह सकें।

कुमार (2021) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों का विश्लेषण करते हुए बताया है कि यह नीति शिक्षक-प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके

अनुसार चार वर्षीय समेकित बी.एड. कार्यक्रम शिक्षक-प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित तथा प्रभावी बनाने में सहायक हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों तथा संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होगी। यूनेस्को (2021) की रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की सफलता उसके शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नवाचार, तकनीकी संसाधनों का उपयोग तथा निरंतर व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षक बदलते शैक्षिक परिवेश के अनुरूप स्वयं को विकसित कर सकें। उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा प्रणाली की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक-शिक्षा में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तुत करती है। तथापि इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों की संरचना, संसाधनों तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2020). **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अग्रवाल, जे.सी. (2018). **शिक्षा का दर्शन एवं समाजशास्त्र**. नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस।
3. शर्मा, आर.ए. (2017). **शिक्षा अनुसंधान एवं सांख्यिकी**. मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।
4. सिंह, बी.पी. (2019). **शिक्षक शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार**. नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन।
5. पाण्डेय, रामशकल. (2016). **शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार**. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर।
6. गुप्ता, एस.पी. (2018). **आधुनिक शिक्षा के सिद्धांत**. इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
7. तिवारी, डी.एन. (2021). **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय शिक्षा व्यवस्था**. नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स।
8. मिश्रा, आर.के. (2021). **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन**. वाराणसी: भारतीय प्रकाशन।
9. त्रिपाठी, आर.एस. (2019). **शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण**. नई दिल्ली: एपीएच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।
10. यादव, के. (2022). **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव**. नई दिल्ली: ज्ञान प्रकाशन।
11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE). (2020). **भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता एवं मानक**. नई दिल्ली।
12. शिक्षा मंत्रालय. (2021). **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की रूपरेखा**. नई दिल्ली: भारत सरकार।
13. कुमार, कृष्ण. (2021). **भारतीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020**. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
14. वर्मा, वी.पी. (2017). **आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान**. नई दिल्ली: विश्व प्रकाशन।
15. चौहान, एस.एस. (2016). **शिक्षा मनोविज्ञान**. मेरठ: आर. लाल बुक डिपो।
16. यूनेस्को. (2021). **शिक्षा का भविष्य और शिक्षक शिक्षा सुधार**. पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन।